NATIONAL HUMAN RIGHTS COMMISSION

TRIBUNE, Chandigarh, 25.6.2025
Page No. 14, Size:(28.31)cms X (11.51)cms.

MPs question absence of FIR in cash-at-judge's house case

ADITI TANDON/
SATYA PRAKASH
TRIBUNE NEWS SERVICE

Seek code of conduct for higher judiciary

NEW DELHI, JUNE 24

Parliamentarians cutting across party lines on Tuesday demanded a code of ethics for higher judiciary and asked why no FIR had been registered in the cash-at-judge's house case despite recovery of burnt wads of currency notes.

The MPs raised these issues at a briefing of the Parliamentary Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice by Secretary, Justice Department on "Judicial processes and reforms".

The briefing covered two subjects — code of conduct for the judges of higher judiciary and judges taking up post-retirement assignments.

Sources said the dominant concern at the meeting was the absence of an FIR in the matter pertaining to recovery of cash from the official residence of Justice Yashwant Varma of the Delhi High Court , who was later transferred to the Allahabad HC.

Many MPs red flagged a missing FIR despite incriminating evidence and asked why the process of removal of the judge had not been initiated even after the in-house probe panel, appointed by the Chief Justice of India, recommended the removal of Justice Varma. This recommendation was based on the panel's conclusion that "bundles of cash" were indeed recovered from the storeroom of his official residence in Delhi and later removed under suspicious circumstances.

The legislators asked the government to draft a comprehensive bill addressing ethical issues involving higher judiciary. They said there should be a cooling off period of five years for judges to be appointed post-retirement. Some MPs also said retired judges should not be nominated as MPs. Incidentally, former CJI Ranjan Gogoi, a member of the parliamentary panel, was absent on Tuesday.

The present legal position on FIRs in matters involving the judiciary is that the police can't register an FIR against a sitting HC or SC judge on their own in view of the Supreme Court's direction in K Veeraswami versus Union of India (1991), in which it was held that such a criminal case can only be filed after consulting the CJI.

"No criminal case shall be registered under Section 154 of the CrPC against a High Court Judge or Chief Justice or a Supreme Court Judge, unless the CJI is consulted in the matter," the top court had ruled.

The Delhi Police could have, however, lodged an FIR without naming anybody and later approached the CJI for his permission, if they wanted to name Justice Varma as an accused in the case.

As far as post retirement appointments of judges go, a slew of existing laws in India prescribe that only a retired judge of the SC or of a HC can be appointed as chairperson and member of a tribunal.

There are several commissions and tribunals such as the NHRC, state human rights commissions, National and State Consumer Disputes Redressal Commissions, Central Administrative Tribunal, Armed Forces Tribunal and National Company Law Appellate Tribunal, in which retired judges are required to be appointed as chairpersons and members.

As regards code of conduct for judges, India has no standalone code. The SC in its full court meeting on May 7, 1997, had adopted two Resolutions — The Restatement of Values of Judicial Life, which lays down certain judicial standards and principles to be observed and followed by the SC and high court Judges; and "In-house procedure" for taking suitable remedial action against judges, who do not follow universally accepted values of judicial life, including those included in the 'Restatement of Values of Judicial Life'.

As per the established "In-house procedure' for the higher judiciary, the CJI is competent to receive complaints against the conduct of SC Judges and the Chief Justices of the HCs. Similarly, the HC Chief Justices are competent to receive complaints against the conduct of HC Judges.

STATESMAN, Delhi, 25.6.2025
Page No. 8, Size:(17.38)cms X (20.65)cms.

Poisonous gas leak deaths: NHRC seeks report from Andhra Pradesh govt

AGENCIES
NEW DELHI, 24 JUNE

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of the death of two workers and injuries to another after inhaling poisonous gas at an effluent waste treatment plant in Andhra Pradesh's Anakapalli.

The apex human rights body issued a notice to the Andhra Pradesh Chief Secretary and the Anakapalli Superintendent of Police, and called for a detailed report on the matter within two weeks.

"The report is expected to include the status of the health of the injured, who was reportedly undergoing treatment at a hospital, and compensation, if any, provided to him and the next of kin of the deceased," said a press statement issued by the NHRC.

Taking note of a news report of the deadly incident of poisonous gas leakage, the human rights commission said the contents of the press report, if true, raise a serious violation of the human rights of the victims.

Two employees died and another was hospitalised after inhaling poisonous gas when they were working during the night shift at an effluent waste treatment plant of a pharmaceutical company in Anakapalli on 11 June.

AMAR UJALA, Delhi, 25.6.2025
Page No. 14, Size:(3.23)cms X (2.95)cms.

आंध्र : फार्मा प्लांट में जहरीली गैस रिसाव, एनएचआरसी ने मांगी रिपोर्ट

नई दिल्ली। भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले के फार्मा प्लांट में जहरीली गैस की घटना का स्वतः संज्ञान लिया है। घटना में दो श्रमिकों की मौत हो गई थी जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया था। इस मामले में आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और अनकापल्ली के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो हफ्ते के अंदर रिपोर्ट मांगी है। एजेंसी

DAINIK JAGRAN (JAGRAN CITY), Delhi, 25.6.2025
Page No. 4, Size:(2.55)cms X (7.86)cms.

एम्स में इंप्लांट उपलब्ध कराने में गड़बड़ी की शिकायत पर एनएचआरसी का नोटिस

नई दिल्ली: एक गैर सरकारी संगठन ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) में शिकायत देकर आरोप लगाया है कि एम्स में मरीजों को रेट कांट्रेक्ट या अमृत फार्मेसी के जरिये ब्रेन इंप्लांट उपलब्ध न कराकर निजी वेंडर से सीधे खरीदने की सलाह दी जा रही है। इस से मरीज तीन से चार गुना महंगे कीमत पर इंप्लांट खरीदने को मजबूर हो रहे हैं। एनएचआरसी ने संज्ञान लेते हुए एम्स के निदेशक व चिकित्सा अधीक्षक को नोटिस जारी कर जांच करने का निर्देश दिया है। आयोग के नोटिस में कहा गया है कि सह्याद्री राइट फोरम ने शिकायत दी है कि एम्स के कुछ डाक्टर मरीजों को इंप्लांट के लिए सीधे प्राइवेट वेंडर के पास भेज रहे हैं। यह अनैतिक और मरीजों के अधिकार का हनन है। शिकायतकर्ता ने आयोग से इस मामले पर कार्रवाई करने की मांग की है। आयोग ने नोटिस में कहा है कि 15 दिन में कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत करें। (राब्यू)

DAINIK BHASKAR, Delhi, 25.6.2025
Page No. 3, Size:(14.71)cms X (11.20)cms.

एम्सः डॉक्टरों पर नियमों का पालन न करने का आरोप, एनएचआरसी से नोटिस

भास्कर न्यूज | नई दिल्ली

गैर सरकारी संस्था ने दर्ज कराई शिकायत

अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) देश का एक प्रमुख चिकित्सा संस्थान है। एम्स के कुछ डॉक्टरों पर नियमों का उल्लंघन कर मरीजों के लिए जीवनरक्षक उपकरण निजी विक्रेताओं से खरीदने के आरोप लगे हैं। यह आरोप भी लगाया कि इन डॉक्टरों ने आवश्यक प्रक्रियाओं का पालन किए बिना, अपनी पसंद के विक्रेताओं से उपकरण खरीदे। आरोप है कि डॉक्टरों ने खरीद प्रक्रिया में पारदर्शिता और नियमों का पालन नहीं किया, जिससे संभावित रूप से वित्तीय अनियमितताएं और गुणवत्तापूर्ण उपकरणों की कमी हो सकती है। मामले की गंभीरता को देखते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने संज्ञान लिया है। आयोग ने एम्स से 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) तलब की है।

एक गैर-सरकारी संस्था सह्याद्रि राइट्स फोरम ने यह चौंकाने वाली शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, एम्स के न्यूरोरेडियोलॉजी विभाग के डॉक्टर, दिमाग की नसों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एक खास इक्विपमेंट फ्लो डायवर्टर, के लिए मरीजों या उनके तीमारदारों को एक निजी वेंडर का फोन नंबर थमा देते थे। यह सीधे तौर पर सरकारी खरीद नियमों का उल्लंघन है। ये नियम इसलिए बनाए गए है ताकि मरीजों को मेडिकल इक्विपमेंट के बाजार में होने वाले लूट से बचाया जा सके और उन्हें सही कीमत पर इलाज मिल सके।

निजी वेंडर ले रहे थे पांच लाखः आरोप है कि फ्लो डायवर्ट के लिए यह निजी वेंडर एम्स के मरीजों से 5 लाख रुपये से अधिक ले रहा था और इसमें टैक्स शामिल नहीं था। वहीं, सरकारी अस्पताल में यह इक्विपमेंट 4 लाख रुपये में मिल रहा था। यानी सीधे-सीधे एक ही इक्विपमेंट के लिए वेंडर एक लाख रुपये से ज्यादा पैसे मांग रहा था। एनएचआरसी ने एम्स डायरेक्टर को भेजे अपने नोटिस में कहा है, शिकायत में लगाए गए आरोप पहली नजर में पीडितों के मानवाधिकारी का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होते हैं। आयोग ने प्रभावित मरीजों के लिए मुआवजे और दोषियों के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है।

NAVODYA TIMES, Delhi, 25.6.2025
Page No. 4, Size:(21.88)cms X (30.94)cms.

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने एम्स से मांगा जवाब

जीवनरक्षक उपकरण खरीदने के लिए निजी वेंडर के पास भेजने की शिकायत

नई दिल्ली, 24 जून (नवोदय टाइम्स): राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एम्स को नोटिस जारी कर जीवनरक्षक उपकरण खरीदने के लिए मरीजों को निजी वेंडर के पास भेजने की शिकायत पर जवाब मांगा है। एक गैर-सरकारी संस्था की तरफ से की गई शिकायत पर आयोग ने 15 दिन के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (एटीआर) तलब की है। दरअसल, एनजीओ की शिकायत में आरोप लगाया गया है कि कुछ डॉक्टरों ने अपनी पसंद के विक्रेताओं से उपकरण खरीदने के लिए कहा और बाकायदा वेंडर का नंबर भी दिया।

एनएचआरसी ने एम्स डायरेक्टर को भेजे नोटिस में कहा है कि शिकायत में लगाए गए आरोप पहली नजर में पीड़ितों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होते हैं। आयोग ने प्रभावित मरीजों के लिए मुआवजे और दोषियों के लिए सख्त कार्रवाई की बात भी कही है।

SANDHYA TIMES, Delhi, 24.6.2025
Page No. 4, Size:(9.60)cms X (7.65)cms.

AIIMS में जिंदगी से खिलवाड़ ?

NHRC ने मांगा जवाब

■ **सान्ध्य टाइम्स ब्यूरो।** ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस (AIIMS) पर भरोसे को तोड़ने वाले गंभीर आरोप लगे हैं। यहां के डॉक्टरों पर आरोप है कि वे नियमों को ताक पर रखकर मरीजों को ब्रेन इम्प्लांट जैसे लाइफ सेविंग इक्विपमेंट एक निजी वेंडर से खरीदने के लिए मजबूर कर रहे थे, जिससे मरीजों को भारी आर्थिक चपत लग रही थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए नैशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन (NHRC) ने संज्ञान लिया है और एम्स से 15 दिनों के भीतर एक्शन टेकन रिपोर्ट (ATR) तलब की है।

क्या है यह पूरा गोरखधंधा?

एक गैर-सरकारी संस्था 'सह्याद्रि राइट्स फोरम' ने यह चौंकाने वाली शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के अनुसार, एम्स के

न्यूरोरेडियोलॉजी विभाग के डॉक्टर, दिमाग की नसों के इलाज में इस्तेमाल होने वाले एक खास इक्विपमेंट 'फ्लो डायवर्टर' के लिए मरीजों या उनके तीमारदारों को एक निजी वेंडर का फोन नंबर थमा देते थे। यह सीधे तौर पर सरकारी खरीद नियमों का उल्लंघन है। ये नियम इसलिए बनाए गए हैं ताकि मरीजों को मेडिकल इक्विपमेंट के बाजार में होने वाली लूट से बचाया जा सके और उन्हें सही कीमत पर इलाज मिल सके। आरोप है कि फ्लो डायवर्टर के लिए यह निजी वेंडर एम्स के मरीजों से 5 लाख रुपये से अधिक ले रहा था और इसमें टैक्स शामिल नहीं था। वहीं, सरकारी अस्पताल में यह इक्विपमेंट 4 लाख रुपये में मिल रहा था। यानी सीधे-सीधे एक ही इक्विपमेंट के लिए वेंडर एक लाख रुपये से ज्यादा पैसे मांग रहा था।

मानवाधिकार आयोग ने माना 'गंभीर उल्लंघन'

NHRC ने एम्स डायरेक्टर को भेजे अपने नोटिस में कहा है, शिकायत में लगाए गए आरोप पहली नजर में पीड़ितों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन प्रतीत होते हैं। आयोग ने प्रभावित मरीजों के लिए मुआवजे और दोषियों के लिए सख्त कार्रवाई की मांग की है। **(नस)**

Tribune

MPs question absence of FIR in cash-at-judge's house case

Seek code of conduct for higher judiciary

https://www.tribuneindia.com/news/india/mps-question-absence-of-fir-in-cash-at-judges-house-case/

ADITI TANDON SATYA PRAKASH New Delhi, Updated At : 03:56 AM Jun 25, 2025 IST

The panel has found some evidence that indicate that the burnt cash was removed from the storeroom on May 15 after a fire incident came to light, say sources. File

Parliamentarians cutting across party lines on Tuesday demanded a code of ethics for higher judiciary and asked why no FIR had been registered in the cash-at-judge's house case despite recovery of burnt wads of currency notes.

The MPs raised these issues at a briefing of the Parliamentary Committee on Personnel, Public Grievances, Law and Justice by Secretary, Justice Department on "Judicial processes and reforms".

The briefing covered two subjects — code of conduct for the judges of higher judiciary and judges taking up post-retirement assignments.

Sources said the dominant concern at the meeting was the absence of an FIR in the matter pertaining to recovery of cash from the official residence of Justice Yashwant Varma of the Delhi High Court , who was later transferred to the Allahabad HC.

Many MPs red flagged a missing FIR despite incriminating evidence and asked why the process of removal of the judge had not been initiated even after the in-house probe panel, appointed by the Chief Justice of India, recommended the removal of Justice Varma. This recommendation was based on the panel's conclusion that "bundles of cash" were indeed recovered from the storeroom of his official residence in Delhi and later removed under suspicious circumstances.

The legislators asked the government to draft a comprehensive bill addressing ethical issues involving higher judiciary. They said there should be a cooling off period of five years for judges to be appointed post-retirement. Some MPs also said retired judges should not be nominated as MPs. Incidentally, former CJI Ranjan Gogoi, a member of the parliamentary panel, was absent on Tuesday.

The present legal position on FIRs in matters involving the judiciary is that the police can't register an FIR against a sitting HC or SC judge on their own in view of the Supreme Court's direction in K Veeraswami versus Union of India (1991), in which it was held that such a criminal case can only be filed after consulting the CJI.

“No criminal case shall be registered under Section 154 of the CrPC against a High Court Judge or Chief Justice or a Supreme Court Judge, unless the CJI is consulted in the matter,” the top court had ruled.

The Delhi Police could have, however, lodged an FIR without naming anybody and later approached the CJI for his permission, if they wanted to name Justice Varma as an accused in the case.

As far as post retirement appointments of judges go, a slew of existing laws in India prescribe that only a retired judge of the SC or of a HC can be appointed as chairperson and member of a tribunal.

There are several commissions and tribunals such as the NHRC, state human rights commissions, National and State Consumer Disputes Redressal Commissions, Central Administrative Tribunal, Armed Forces Tribunal and National Company Law Appellate Tribunal, in which retired judges are required to be appointed as chairpersons and members.

As regards code of conduct for judges, India has no standalone code. The SC in its full court meeting on May 7, 1997, had adopted two Resolutions — The Restatement of Values of Judicial Life, which lays down certain judicial standards and principles to be observed and followed by the SC and high court Judges; and “In-house procedure” for taking suitable remedial action against judges, who do not follow universally accepted values of judicial life, including those included in the ‘Restatement of Values of Judicial Life’.

As per the established “In-house procedure’ for the higher judiciary, the CJI is competent to receive complaints against the conduct of SC Judges and the Chief Justices of the HCs. Similarly, the HC Chief Justices are competent to receive complaints against the conduct of HC Judges.

Jurist

India urged to cease `illegal' and `inhuman' punitive demolitions

https://www.jurist.org/news/2025/06/india-urged-to-cease-illegal-and-inhuman-punitive-demolitions/

Arshiya Gupta | National Law U. Delhi, IN

June 24, 2025 12:31:45 pm

Independent human rights experts have issued a stark warning, calling on India to immediately put an end to its practice of arbitrary and punitive demolitions that disproportionately affect low-income households, minorities, and migrants. According to the UN Special Rapporteur on the right to housing, India is leading the front in illegal home demolitions. These actions are denounced as an "aggravated form of human rights violation, and are especially egregious when they target or discriminate against minorities or marginalised communities".

According to the UN experts, the demolitions have been utilized by state authorities since 2020 as a form of collective and arbitrary punishment following communal violence and protests. Between 2020 and 2022, over 2,840 properties, predominantly belonging to Muslims, were destroyed across various Indian states. This aligns with observations from Human Rights Watch, which noted in October 2022 that Indian authorities are increasingly employing summary and abusive punishments against Muslims, often "blatantly disregarding the rule of law" and sending a message of discrimination and attack.

Reports indicate that public authorities and politicians have at times incited communal violence against religious minorities, with state actors allegedly supporting, participating in, or failing to investigate violence by Hindu nationalist vigilante groups due to their links to the ruling Bharatiya Janata Party (BJP). Attacks on mosques have also been reported, with some allegedly bulldozed for being "illegal structures". Moreover, historically disadvantaged and marginalized communities such as Scheduled Castes (SCs) and Scheduled Tribes (STs) face rampant caste-based discrimination, with employers sometimes restricting their access to basic facilities and places of worship.

India has a National Human Rights Commission (NHRC), which is recognized for its full compliance with UN-mandated Paris Principles and has been accredited with an 'A' status by the Global Alliance of National Human Rights Institutions. The NHRC actively pursues a "human rights-centered approach" and takes suo motu cognizance of serious matters, including police high-handedness and custodial deaths, which are also areas of its focus. However, reports also indicate issues with police effectiveness, including inadequate training, limited resources, corruption, and bias, particularly affecting underprivileged groups like SCs and STs. Authorities have also imposed temporary internet blackouts, ostensibly to maintain law and order, but which have in practice been used to suppress dissent.

Judicial bodies have condemned these demolition practices. The Supreme Court's Division Bench in April 2025 deemed the demolition of six homes in Prayagraj, Uttar Pradesh, "illegal," "high-handed," and "inhuman," ordering significant compensation. The court criticized the practice of providing "less than 24 hours" notice, often merely "affixed" to homes, rather than ensuring personal service, which led to people losing their houses. This landmark order facilitates viewing punitive demolitions not only as violations of the right to shelter but also through the lens of cruelty and torture.

The New Indian Experss

Gopalpur gangrape: NHRC seeks report from chief secretary, DGP in two weeks

The Commission has observed that the content of the media report, if true, raise a serious issue of violation of human rights.

https://www.newindianexpress.com/states/odisha/2025/Jun/23/gopalpur-gangrape-nhrc-seeks-report-from-chief-secretary-dgp-in-two-weeks

Express News Service | Updated on: 24 Jun 2025, 10:03 am

2 min read

BHUBANESWAR: The National Human Rights Commission (NHRC) on Monday took suo motu cognizance of the gang-rape of a 20-year-old college student in Gopalpur on June 15, and directed chief secretary Manoj Ahuja and DGP YB Khurania to submit a detailed report within two weeks.

Issuing notices to the chief secretary and DGP, the rights panel specified their reports should include the status of investigation in the case, the victim's health condition, and if any compensation/ counselling was provided to her.

The student was raped by around 10 youths, including four minors, at Gopalpur sea beach where she had been along with a male friend. The accused overpowered her friend and sexually assaulted her. The incident has raised a serious issue of violation of human rights, the NHRC noted.

Last week, the National Commission for Women (NCW) asked DGP to conduct a swift and time-bound investigation into the incident. The NCW chairperson Vijaya K Rahatkar also asked the DGP to ensure that compensation was paid to the rape survivor under section 396 of the Bharatiya Nyaya Sanhita (BNS).

CAW&CW has collected digital and DNA evidence in the case

Briefing the mediapersons on the day, Crime Branch DG Vinaytosh Mishra said on the direction of the DGP, Crime Against Women and Children Wing (CAW&CW) immediately took up the investigation of the case. "The local police had arrested the six youths and detained the four juveniles. Our priority is to make the investigation watertight and ensure the culprits are punished as per the law," he said.

The CAW&CW has collected digital and DNA evidence and seized CCTV footage of the 10 youths in the area before and after committing the crime. "Their mobile phones have been confiscated which also contain vital evidence. We have requested the State Forensic Science Laboratory (SFSL) to extract the digital data and submit the reports at the earliest so that the charge sheet is filed without any delay," said Mishra.

PIB

NHRC, India takes suo motu cognizance of the reported death of two workers and injuries to another after inhaling poisonous gas at an effluent waste treatment plant of a Pharmaceutical company in Anakapalli district of Andhra Pradesh

Issues notices to the Chief Secretary, Government of Andhra Pradesh and the Superintendent of Police, Anakapalli, calling for a detailed report on the matter within two weeks

The report expected to include the status of the health of the injured and compensation, if any, provided to him and the next of kin of the deceased

https://www.pib.gov.in/PressReleasePage.aspx?PRID=2139127

Posted On: 24 JUN 2025 12:01PM by PIB Delhi

The National Human Rights Commission (NHRC), India, has taken suo motu cognizance of a media report that two employees died and another was hospitalized after inhaling poisonous gas when they were working during the night shift at an effluent waste treatment plant of a Pharmaceutical company in Anakapalli district of Andhra Pradesh, on 11th June, 2025. Reportedly, the victim workers collapsed after inhaling the poisonous gas, suspected to have been released during the waste treatment process.

The Commission has examined that the contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of the human rights of the victims. Therefore, the Commission has issued notices to the Chief Secretary, Government of Andhra Pradesh and the Superintendent of Police, Anakapalli, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

The report is expected to include the status of the health of the injured, who was reportedly undergoing treatment at a hospital and compensation, if any, provided to him and the next of kin of the deceased.

*****

NSK

(Release ID: 2139127)

Times of India

NHRC seeks report on pharma plant gas leak

https://timesofindia.indiatimes.com/city/vijayawada/nhrc-seeks-report-on-pharma-plant-gas-leak/articleshow/122053175.cms

TNN | Jun 24, 2025, 10.47 PM IST

Visakhapatnam: The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognizance of a media report stating that two employees died and another person was hospitalised after inhaling poisonous gas during their night shift at an effluent waste treatment plant of a pharmaceutical company in Anakapalli district on June 11. According to reports, the workers collapsed after inhaling the poisonous gas, which is suspected to have been released during the waste treatment process.

The commission has determined that the news report, if accurate, raises grave concerns over possible violations of the victims' human rights. Notices have been served to AP chief secretary and Anakapalli superintendent of police (SP), seeking a detailed report on the incident within two weeks.

It may be recalled that Parimi Chandrasekhar (32), assistant manager in safety wing of the pharma company, a native of Telangana, and Saragadam Kumar (25), shift safety officer and a native of Munagapaka in Anakapalli district, lost their lives, while 37-year-old Naidu Bhansali (helper), from Odisha, was hospitalised following suspected inhalation of poisonous fumes at Sai Sreyas Pharmaceutical Private Limited, located within Jawaharlal Nehru Pharma City at Parawada in Anakapalli district on June 11.

The factories department is ascertaining the cause of the accident. Authorities suspect that the three men inhaled hydrogen sulphide (H2S), a colourless toxic substance, which was allegedly released from the effluent treatment plant as they were checking the levels within the facility.

The report is expected to cover the current status of the injured & compensation provided to him and to kin of the deceased

Economic Times

NHRC takes suo moto cognisance of toxic gas incident at Andhra Pradesh pharma plant, seeks report

https://economictimes.indiatimes.com/news/india/nhrc-takes-suo-moto-cognisance-of-toxic-gas-incident-at-andhra-pradesh-pharma-plant-seeks-report/articleshow/122042643.cms?from=mdr

ANI | Last Updated: Jun 24, 2025, 01:03:00 PM IST

Synopsis

The National Human Rights Commission (NHRC) has addressed a notice to Andhra Pradesh officials following a toxic gas leak at a pharmaceutical company in Anakapalli district, resulting in the death of two workers and critical injury to another. The incident occurred during waste processing, prompting concerns over human rights violations.

IANS

The National Human Rights Commission (NHRC) of India has taken suo moto cognisance of media reports concerning the death of two workers and the critical injury of another due to toxic gas exposure at an effluent treatment unit of a pharmaceutical company in Andhra Pradesh's Anakapalli district.

The incident took place during the night shift on 11 June 2025, when the workers reportedly collapsed after inhaling poisonous fumes suspected to have been emitted during waste processing operations.

Citing serious concerns over potential human rights violations, the Commission has issued a notice to the Chief Secretary of Andhra Pradesh and the Superintendent of Police, Anakapalli, seeking a comprehensive report within two weeks.

The NHRC has requested specific details regarding the condition of the hospitalised worker and any compensation provided to him or to the families of the deceased.

Separately, officials confirmed that at least two workers died on the spot after inhaling toxic gases at a pharmaceutical facility in Jawaharlal Nehru Pharma City, Anakapalle district. The gas leak occurred when the workers opened a valve near a tank. The bodies were transferred to King George Hospital in Visakhapatnam.

Telangana Today

NHRC seeks report from Andhra Pradesh on toxic gas deaths at pharma plant

The NHRC has issued notices to the Andhra Pradesh government and police over the deaths of two workers and the hospitalisation of another following a gas leak at a pharma waste treatment plant in Anakapalli.

https://telanganatoday.com/nhrc-seeks-report-from-andhra-pradesh-on-toxic-gas-deaths-at-pharma-plant

By PTI | Published Date - 24 June 2025, 06:09 PM

New Delhi:The National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday said it has issued notices to the government of Andhra Pradesh and a senior police officer over reports that two employees died and another was hospitalised after inhaling poisonous gas while working at a waste treatment plant of a pharmaceutical company in Anakapalli district.

The NHRC has examined that the content of the news report, if true, raise serious issues of violation of the human rights of the victims.

The Commission in a statement said it has taken “suo motu cognisance of a media report that two employees died and another was hospitalised after inhaling poisonous gas when they were working during the night shift at an effluent waste treatment plant of a pharmaceutical company in Anakapalli district of Andhra Pradesh, on 11th June”.

Reportedly, the victims collapsed after inhaling the poisonous gas, suspected to have been released during the waste treatment process, it said.

Therefore, the Commission has issued notices to the chief secretary, of the government of Andhra Pradesh and the superintendent of police of Anakapalli, seeking a detailed report in two weeks, the rights panel said.

The report is expected to include the status of the health of the injured, who was reportedly undergoing treatment at a hospital and compensation, if any, provided to him and the next of kin of the deceased, it added.

Devdiscourse

NHRC Takes Action: Inquiry Launched Over Toxic Gas Tragedy in Andhra Pradesh

The NHRC has issued notices to Andhra Pradesh government officials following reports of two deaths and one hospitalization due to poisonous gas at a pharmaceutical waste treatment plant. The Commission has requested a detailed report on the incident and the victims' conditions within two weeks.

https://www.devdiscourse.com/article/law-order/3479648-nhrc-takes-action-inquiry-launched-over-toxic-gas-tragedy-in-andhra-pradesh

Devdiscourse News Desk | New Delhi | Updated: 24-06-2025 16:21 IST | Created: 24-06-2025 16:21 IST

The National Human Rights Commission (NHRC) has called for accountability from the Andhra Pradesh government after a tragic incident at a pharmaceutical company's waste treatment plant resulted in two deaths and one serious injury. The incident, which took place in Anakapalli district, exposes potential human rights violations.

According to reports, the victims were exposed to poisonous gas during their night shift, speculated to have originated during the waste treatment process at the plant. The NHRC has issued a notice to the Andhra Pradesh government and local law enforcement, seeking a comprehensive report on the situation.

The NHRC's notice demands details on the health condition of the hospitalized employee, alongside information on any compensation granted to the victims' families. The Commission has emphasized the urgency of this inquiry, setting a two-week deadline for the required documentation.

(With inputs from agencies.)

Medical Dialogues

Deadly pharma plant incident: NHRC seeks report from Andhra Govt, Chief Secretary and Anakapalli Superintendent of Police

https://medicaldialogues.in/news/industry/pharma/deadly-pharma-plant-incident-nhrc-seeks-report-from-andhra-govt-chief-secretary-and-anakapalli-superintendent-of-police-150521

\Written by Ruchika Sharma Published On 2025-06-24T16:25:33+05:30 | Updated On 24 Jun 2025 4:25 PM IST

New Delhi: The National Human Rights Commission (NHRC), India, has taken suo motu cognizance of a media report that two employees died and another was hospitalized after inhaling poisonous gas when they were working during the night shift at an effluent waste treatment plant of a Pharmaceutical company in Anakapalli district of Andhra Pradesh, on 11th June, 2025.

Reportedly, the victim workers collapsed after inhaling the poisonous gas, suspected to have been released during the waste treatment process.

The Commission has examined that the contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of the human rights of the victims. Therefore, the Commission has issued notices to the Chief Secretary, Government of Andhra Pradesh and the Superintendent of Police, Anakapalli, calling for a detailed report on the matter within two weeks.

The report is expected to include the status of the health of the injured, who was reportedly undergoing treatment at a hospital and compensation, if any, provided to him and the next of kin of the deceased.

UNI

NHRC notice to Andhra Pradesh CS, SP in fatal gas inhalation case

https://www.uniindia.com/news/india/rights-nhrc-gas-inhalation/3497718.html

India Posted at: Jun 24 2025 3:04PM

New Delhi, Jun 24 (UNI) The National Human Rights Commission (NHRC) on Monday issued notice to Andhra Pradesh Chief Secretary and Superintendent of Police, Anakapalli district in a case pertaining to two deaths due to inhaling of poisonous gas at a pharma firm.

The NHRC has asked the authorities to submit a report within two weeks, giving details on health of the injured in the mishap, who was reportedly undergoing treatment at a hospital.

In a statement issued here, the NHRC said that it has “taken suo motu cognizance of a media report that two employees died and another was hospitalized after inhaling poisonous gas when they were working during the night shift at an effluent waste treatment plant of a Pharmaceutical company in Andhra Pradesh’s Anakapalli district on June 11, 2025.”

The workers reportedly collapsed after inhaling the poisonous gas, suspected to have been released during the waste treatment process, noted the NHRC.

“The Commission has examined that the contents of the news report, if true, raise serious issues of violation of the human rights of the victims,” said the statement.

UNI AJ RKM

The News Minute

Poisonous gas leak deaths: NHRC seeks report from Andhra govt

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of the death of two workers and injuries to another after inhaling poisonous gas at an effluent waste treatment plant in Andhra Pradesh's Anakapalli.

https://www.thenewsminute.com/news/poisonous-gas-leak-deaths-nhrc-seeks-report-from-andra-govt

Written by: IANS Published on: 24 Jun 2025, 1:43 pm

The National Human Rights Commission (NHRC) has taken suo motu cognisance of the death of two workers and injuries to another after inhaling poisonous gas at an effluent waste treatment plant in Andhra Pradesh's Anakapalli.

The apex human rights body issued a notice to the Andhra Pradesh Chief Secretary and the Anakapalli Superintendent of Police, and called for a detailed report on the matter within two weeks.

"The report is expected to include the status of the health of the injured, who was reportedly undergoing treatment at a hospital, and compensation, if any, provided to him and the next of kin of the deceased," said a press statement issued by the NHRC.

Taking note of a news report of the deadly incident of poisonous gas leakage, the human rights commission said the contents of the press report, if true, raise a serious violation of the human rights of the victims.

Two employees died and another was hospitalised after inhaling poisonous gas when they were working during the night shift at an effluent waste treatment plant of a pharmaceutical company in Anakapalli on June 11.

Reportedly, the victim workers collapsed after inhaling the poisonous gas, suspected to have been released during the waste treatment process.

Established under the Protection of Human Rights Act, 1993, the NHRC, an autonomous statutory body, is an embodiment of India's concern for the promotion and protection of human rights. Its primary role is to protect and promote human rights, defined as the rights relating to life, liberty, equality, and dignity of individuals guaranteed by the Constitution or embodied in the International Covenants and enforceable by courts in India.

The apex human rights body has the power to take suo motu (on its own motion) action based on media reports, public knowledge or other sources, without receiving a formal complaint of human rights violations.

SCC Online

NHRC takes suo motu cognizance of reported death of 2 workers after suspected poisonous gas leak at Pharma Unit at Anakapalli

The NHRC noted that the victim workers collapsed after inhaling the poisonous gas, suspected to have been released during the waste treatment process

https://www.scconline.com/blog/post/2025/06/24/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-worker-deaths-at-andhra-pradesh-pharma-plant/

Published on June 24, 2025 By Editor

National Human Rights Commission: On 24-06-2025, the National Human Rights Commission ('NHRC') took suo motu cognizance of a media report highlighting an incident on 11-06-2025 where two employees died, and another was hospitalized after inhaling poisonous gas when they were working during the night shift at an effluent waste treatment plant of a pharmaceutical company in Anakapalli district of Andhra Pradesh. The report indicated that the victim workers collapsed after inhaling the poisonous gas, suspected to have been released during the waste treatment process.

The Commission noted that if the contents of the media report were true, it raised serious issues of violation of the human rights of the victims. Consequently, it issued notices to the Chief Secretary, Government of Andhra Pradesh, and the Superintendent of Police, Anakapalli, requesting a detailed report on the matter within two weeks. The report is expected to cover the status of the health of the injured, who was reportedly undergoing treatment at a hospital, and compensation, if any, provided to him and the next of kin of the deceased.

UP Kiran

मानवाधिकार आयोग सख्त: जहरीली गैस रिसाव से हुई मौतों पर आंध्र सरकार को नोटिस

https://upkiran.org/Human-Rights-Commission-strict-Notice-to-Andhra-government-on-deaths-due-to-poisonous-gas-leak

राष्ट्रीय 2025-06-24 13:58:00

Up Kiran, Digital Desk: आंध्र प्रदेश में एक दुखद घटना सामने आई है, जहाँ एक औद्योगिक इकाई से संदिग्ध जहरीली गैस के रिसाव के कारण तीन लोगों की मौत हो गई और एक व्यक्ति घायल हो गया। इस गंभीर मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) ने राज्य सरकार से विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

यह दिल दहला देने वाली घटना अनंतपुर जिले में हुई, जहाँ कथित तौर पर एक औद्योगिक इकाई से हुए गैस रिसाव ने एक माँ और उसकी दो बेटियों की जान ले ली, जबकि परिवार का एक और सदस्य घायल हो गया।

NHRC ने मीडिया रिपोर्टों के आधार पर इस घटना का संज्ञान लिया है और इसे 'मानव अधिकारों का गंभीर उल्लंघन' माना है, विशेष रूप से 'जीवन के अधिकार' का। आयोग ने चिंता व्यक्त की कि जहरीली गैस का रिसाव औद्योगिक सुरक्षा मानदंडों और पर्यावरणीय नियमों के घोर उल्लंघन का संकेत देता है।

इस मामले की गंभीरता को देखते हुए, NHRC ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और पुलिस महानिदेशक (DGP) को नोटिस जारी किया है। आयोग ने उनसे चार हफ्तों के भीतर एक विस्तृत रिपोर्ट पेश करने का निर्देश दिया है। इस रिपोर्ट में घटना के कारण, जिम्मेदारियों का निर्धारण, पीड़ितों को दिए गए मुआवजे और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए उठाए गए कदमों का पूरा विवरण होना चाहिए।

यह घटना एक बार फिर औद्योगिक क्षेत्रों में सुरक्षा उपायों की कमी और पर्यावरण प्रदूषण के गंभीर परिणामों की याद दिलाती है। NHRC का यह कदम पीड़ितों के लिए न्याय सुनिश्चित करने और भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने की दिशा में महत्वपूर्ण है।

Janta se Rishta

NHRC ने आंध्र प्रदेश के फार्मा प्लांट में जहरीली गैस की घटना का स्वतः संज्ञान लिया, रिपोर्ट मांगी

https://jantaserishta.com/national/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-poisonous-gas-incident-in-andhra-pradesh-pharma-plant-seeks-report-4103263

Rani Sahu 24 June 2025 1:57 PM

New Delhi नई दिल्ली : भारत के राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में एक दवा कंपनी की अपशिष्ट उपचार इकाई में जहरीली गैस के संपर्क में आने से दो श्रमिकों की मौत और एक अन्य के गंभीर रूप से घायल होने से संबंधित मीडिया रिपोर्टों का स्वतः संज्ञान लिया है।

यह घटना 11 जून 2025 को रात की पाली के दौरान हुई, जब कथित तौर पर अपशिष्ट प्रसंस्करण कार्यों के दौरान निकलने वाले जहरीले धुएं की वजह से श्रमिक बेहोश हो गए। संभावित मानवाधिकार उल्लंघनों पर गंभीर चिंताओं का हवाला देते हुए, आयोग ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और अनकापल्ली के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर एक व्यापक रिपोर्ट मांगी है।

एनएचआरसी ने अस्पताल में भर्ती कर्मचारी की स्थिति और उसे या मृतक के परिवारों को दिए जाने वाले किसी भी मुआवजे के बारे में विशिष्ट विवरण मांगा है। अलग से, अधिकारियों ने पुष्टि की कि अनकापल्ले जिले के जवाहरलाल नेहरू फार्मा सिटी में एक दवा सुविधा में जहरीली गैसों के कारण कम से कम दो श्रमिकों की मौके पर ही मौत हो गई। गैस रिसाव तब हुआ जब श्रमिकों ने एक टैंक के पास एक वाल्व खोला। शवों को विशाखापत्तनम के किंग जॉर्ज अस्पताल में स्थानांतरित कर दिया गया। (एएनआई)

Janta se Rishta

जहरीली गैस रिसाव से मौतें: एनएचआरसी ने आंध्र सरकार से रिपोर्ट मांगी

https://jantaserishta.com/local/andhra-pradesh/poisonous-gas-leak-deaths-nhrc-seeks-report-from-andra-govt-4103158

Bharti Sahu 24 June 2025 1:25 PM

जहरीली गैस

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली में एक अपशिष्ट उपचार संयंत्र में जहरीली गैस की चपेट में आने से दो श्रमिकों की मौत और एक अन्य के घायल होने का स्वतः संज्ञान लिया है शीर्ष मानवाधिकार निकाय ने आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव और अनकापल्ली के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी किया और दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी।एनएचआरसी द्वारा जारी एक प्रेस बयान में कहा गया है, "रिपोर्ट में घायल व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति, जिसका कथित तौर पर एक अस्पताल में इलाज चल रहा था, और उसे और मृतक के परिजनों को दिए गए मुआवजे, यदि कोई हो, के बारे में जानकारी शामिल होने की उम्मीद है।"

जहरीली गैस रिसाव की घातक घटना की एक समाचार रिपोर्ट पर ध्यान देते हुए, मानवाधिकार आयोग ने कहा कि प्रेस रिपोर्ट की सामग्री, यदि सत्य है, तो पीड़ितों के मानवाधिकारों का गंभीर उल्लंघन करती है।11 जून को अनकापल्ली में एक दवा कंपनी के अपशिष्ट उपचार संयंत्र में रात्रि पाली में काम करते समय जहरीली गैस की चपेट में आने से दो कर्मचारियों की मौत हो गई और एक अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया।कथित तौर पर, पीड़ित कर्मचारी जहरीली गैस की चपेट में आने से बेहोश हो गए

जिसके बारे में संदेह है कि यह गैस अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया के दौरान छोड़ी गई थी।मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 के तहत स्थापित, NHRC, एक स्वायत्त वैधानिक निकाय है, जो मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण के लिए भारत की चिंता का प्रतीक है। इसकी प्राथमिक भूमिका मानवाधिकारों की रक्षा और प्रचार करना है, जिसे संविधान द्वारा गारंटीकृत या अंतर्राष्ट्रीय वाचाओं में सन्निहित व्यक्तियों के जीवन, स्वतंत्रता, समानता और सम्मान से संबंधित अधिकारों के रूप में परिभाषित किया गया है और भारत में न्यायालयों द्वारा लागू किया जा सकता है।सर्वोच्च मानवाधिकार निकाय को मानवाधिकार उल्लंघन की औपचारिक शिकायत प्राप्त किए बिना, मीडिया रिपोर्टों, सार्वजनिक जानकारी या अन्य स्रोतों के आधार पर स्वप्रेरणा से कार्रवाई करने का अधिकार है।

Univarta

जहरीली गैस रिसाव मामले में आंध्र प्रदेश के मुख्य सचिव, पुलिस अधीक्षक को एनएचआरसी का नोटिस

https://www.univarta.com/nhrc-issues-notice-to-andhra-pradesh-chief-secretary-superintendent-of-police-in-toxic-gas-leak-case/india/news/3497873.html

भारत Posted at: Jun 24 2025 6:16PM

नयी दिल्ली,24 जून (वार्ता) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने मंगलवार को एक फार्मा कंपनी में जहरीली गैस के कारण दो लोगों की मौतों से संबंधित मामले में आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और अनकापल्ली के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी करके दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी। एनएचआरसी ने अधिकारियों से दो सप्ताह के भीतर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा है जिसमें दुर्घटना में घायल हुए एक व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में विस्तृत जानकारी मांगी गयी है। घायल का एक अस्पताल में पर इलाज चल रहा है।

In samachar

NHRC ने आंध्र प्रदेश में जहरीली गैस के कारण दो श्रमिकों की मौत और एक अन्य के घायल होने की खबर का स्वतः संज्ञान लिया

https://insamachar.com/nhrc-takes-suo-motu-cognizance-of-news-of-death-of-two-workers-and-injury-of-another-due-to-poisonous-gas-in-andhra-pradesh/

Editor Posted on 24 जून 2025

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने एक मीडिया रिपोर्ट का स्वत: संज्ञान लिया है कि 11 जून, 2025 को आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में एक दवा कंपनी के अपशिष्ट उपचार संयंत्र में रात्रि पाली के दौरान काम करते समय जहरीली गैस की वजह से दो कर्मचारियों की मौत हो गई और एक अन्य को अस्पताल में भर्ती कराया गया। कथित तौर पर, पीड़ित कर्मचारी जहरीली गैस की वजह से बेहोश हो गए, ऐसा संदेह है कि यह गैस अपशिष्ट उपचार प्रक्रिया के दौरान छोड़ी गई थी।

आयोग ने जांच की है कि अगर समाचार रिपोर्ट की सामग्री सच है, तो पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन का गंभीर मुद्दा उठाती है। इसलिए, आयोग ने आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और अनकापल्ली के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह के भीतर मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

रिपोर्ट में घायल व्यक्ति के स्वास्थ्य की स्थिति, जिसका कथित तौर पर अस्पताल में इलाज चल रहा है, तथा उसे और मृतक के निकटतम संबंधी को यदि कोई मुआवजा दिया गया है, तो उसका विवरण भी शामिल होने की उम्मीद है।

The Print Hindi

मानवाधिकार आयोग ने जहरीली गैस से दो कर्मचारियों की मौत के मामले में आंध्र प्रदेश सरकार को नोटिस दिया

https://hindi.theprint.in/india/human-rights-commission-issues-notice-to-andhra-pradesh-government-over-death-of-two-employees-due-to-poisonous-gas/834299/?amp

भाषा 24 जून, 2025

नयी दिल्ली, 24 जून (भाषा) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने मंगलवार को कहा कि उसने आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में एक दवा कंपनी के अपशिष्ट शोधन संयंत्र में काम करते समय जहरीली गैस की वजह से दो कर्मचारियों की मौत और एक अन्य के घायल होने की खबरों पर राज्य सरकार और एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी को नोटिस जारी किया है।

आयोग ने कहा कि अगर समाचार की सामग्री सही है, तो पीड़ितों के मानवाधिकारों के उल्लंघन के गंभीर मुद्दे खड़े होते हैं।

आयोग ने एक बयान में कहा कि उसने "11 जून को आंध्र प्रदेश के अनकापल्ली जिले में एक दवा कंपनी के अपशिष्ट शोधन संयंत्र में रात की पाली में काम करते समय जहरीली गैस की वजह से दो कर्मचारियों की मौत और एक अन्य को अस्पताल में भर्ती कराने संबंधी खबर पर स्वतः संज्ञान लिया है।"

इसमें कहा गया है कि कथित तौर पर, पीड़ितों की जहरीली गैस की वजह से मौत हो गई, जिसके बारे में संदेह है कि यह गैस अपशिष्ट शोधन प्रक्रिया के दौरान निकली थी।

मानवाधिकार आयोग ने कहा कि इसलिए, उसने आंध्र प्रदेश सरकार के मुख्य सचिव और अनकापल्ली के पुलिस अधीक्षक को नोटिस जारी कर दो सप्ताह में विस्तृत रिपोर्ट मांगी है।

इसमें कहा गया है कि रिपोर्ट में उस घायल के स्वास्थ्य की स्थिति का उल्लेख हो सकता है, जिसका कथित तौर पर अस्पताल में इलाज चल रहा है तथा उसे और मृतक के निकटतम संबंधी को यदि कोई मुआवजा दिया गया है, तो उसका विवरण भी शामिल होने की उम्मीद है।

भाषा वैभव दिलीप

दिलीप

यह खबर 'भाषा' न्यूज़ एजेंसी से 'ऑटो-फीड' द्वारा ली गई है. इसके कंटेंट के लिए दिप्रिंट जिम्मेदार नहीं है.

The Indian Express

NHRC takes cognisance of Etawah tonsuring incident, Akhilesh calls it `attack on PDA'

Four accused arrested, sent to jail after FIR registered against them, say police

https://indianexpress.com/article/cities/lucknow/nhrc-takes-cognisance-of-etawah-tonsuring-incident-akhilesh-calls-it-attack-on-pda-10086524/

By: Express News Service | Lucknow | June 25, 2025 01:24 IST

3 min read

Taking cognisance of an incident involving some "upper caste" men assaulting a kathavachak (religious speaker) and his associate from the Yadav community and tonsuring their heads, the National Human Rights Commission (NHRC) on Tuesday issued a notice to the Etawah district police and directed to submit an action taken report.

The development came a day after a video of the incident went viral.

Four accused have been arrested and sent to jail after an FIR was registered in the matter, police said.

The accused were identified as Nikki Awasthi, 30, Pratham Dubey, 24, Ashish Tiwari, 21 and Uttam Awasthi, 19.

The alleged incident took place at Dadarpur village on Saturday (June 21) after the villagers objected to the kathavachak, Mukut Munni, identifying himself as a Brahmin.

The NHRC sought the action taken report from the Etawah Senior Superintendent of Police (SSP) on the basis of a complaint filed by Bhopal-based Dr Ambedkar Jankalyan Samiti, which alleged the religious speaker and his associate from backward class were assaulted, their heads tonsured and human urine was thrown at them.

Also, they were forced to rub their nose at the feet of a woman and their instruments were damaged, it was alleged.

"The allegations made in the complaint prima facie seem to be a serious violation of human rights of the victims," the commission observed in its notice.

Mukut Munni said the incident took place after he informed the villagers about his caste.

In a press statement, the police said the social media team at the police headquarters on Monday evening received a tweet through X, in which a video of tonsuring of a kathavachak was attached. Taking cognizance of the tweet, it was forwarded to Etawah district for necessary action, they said.

SSP Brijesh Kumar Srivastava said, “A video of villagers misbehaving with two individuals and cutting their hair against their will surfaced. The accused were identified with the help of the video.”

Claiming it was an attack on PDA, Akhilesh Yadav said, “Members of the PDA family are being intimidated. If Bhagwat Katha is for everyone to listen to then everyone can recite it as well. Bhagwat Katha is related to Lord Krishna and if his true followers would be stopped from reciting it then we will not tolerate this disrespect.”

The SP chief alleged that some people want to have a monopoly on the recitation of kathas, saying, “If such people have hostility towards PDA then they should stop taking donations from the community.”

Earlier in the day, Uttar Pradesh Tourism Minister Jaiveer Singh said unnecessary hype should not be given to the incident as the accused have been arrested.

“I believe that caste has no privilege over merit and efficiency. One can do anything based on their ability. The incident is unfortunate. An FIR has been registered against the accused. There is no need to give this incident a political turn as no injustice towards anyone would be done under this government,” the minister said, claiming that Akhilesh “sees PDA in everything”.

Dainik Bhaskar

ब्राह्मणों ने जिस कथावाचक को पीटा...अखिलेश ने उसे सम्मानित किया:इटावा में ब्राह्मणों ने कहा- महिलाओं से छेड़खानी की; यादवों ने महासभा बुलाई

https://www.bhaskar.com/local/uttar-pradesh/news/etawah-yadav-katha-vachak-beaten-by-brahmin-akhilesh-yadav-press-conference-135302130.html

लखनऊ 2 घंटे पहले

यूपी के इटावा में कथावाचक की पिटाई का मामला यादव बनाम ब्राह्मण होता जा रहा है। **राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग** ने इटावा के SSP से 10 दिन के भीतर कार्रवाई की रिपोर्ट तलब की है।

अखिलेश यादव ने आज, सोमवार को कथावाचक और उनके साथियों को लखनऊ बुलाया। उन्हें ढोलक और हारमोनियम गिफ्ट की, कथा भी कहलवाई। 51-51 हजार रुपए देने का ऐलान किया। 21-21 हजार रुपए लिफाफे में मौके पर दिए।

अखिलेश ने कहा- प्रभुत्ववादी सीमाएं लांघ गए हैं। ये वर्चस्ववादी लोग सिर तक मुड़वा दे रहे हैं, रातभर पीटते हैं, ढोलक छीन लेते हैं और पैसों की मांग करते हैं। आखिर ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग ताकत कहां से पा रहे हैं? यह सरकार हार्टलेस है, हर असंवैधानिक काम का समर्थन करती है।

वहीं, इटावा में ब्राह्मण महासभा ने SSP बृजेश कुमार श्रीवास्तव से मुलाकात की। कथावाचकों ने अपनी जाति छुपाई। धार्मिक भावना भड़काई। महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। चेतावनी दी कि यदि जल्द कथावाचकों पर पुलिस ने एक्शन नहीं लिया तो आंदोलन किया जाएगा।

इस मामले में विश्व यादव परिषद भी कूद आया है। संगठन के अध्यक्ष अवधेश यादव ने 25 जून को 'चलो इटावा' नाम से महासभा बुलाई है। अब विस्तार से पढ़िए....

पहले लखनऊ में अखिलेश की प्रेस कॉन्फ्रेंस

लोग मर रहे, आप अपनी नजर उतरवा रहे: शाह पर तंज अखिलेश ने अमित शाह का बिना नाम लिए तंज कसा। कहा- नजर उतारने का तरीका तो हमने और आपने देखा ही। बस बच ही गया कोई, बिजली कटने से अस्पताल में लोग मर रहे और आप अपनी नजर उतरवा रहे हो। दरअसल, रविवार शाम अमित शाह, सीएम योगी के साथ वाराणसी के काल भैरव मंदिर पहुंचे थे। यहां दर्शन-पूजन के दौरान एक पुजारी ने शाह की दंड से नजर उतारी थी।

अखिलेश की 5 बड़ी बातें

1- कथावाचन के लिए कानून बना दो... इस सरकार का रवैया क्या है? इसका रास्ता क्या है? कई मौकों पर मैंने कहा है- सरकार हार्टलेस है। हर असंवैधानिक काम का समर्थन करती है। बाबा साहेब के संविधान की प्रस्तावना के हिसाब से फैसले लेने लगें तो जिनके साथ अन्याय हो रहा है, उन्हें न्याय मिलने लगे। सरकार में बैठे लोग लगातार अन्याय करा रहे हैं।

वर्चस्ववादी लोगों को इतनी तकलीफ है तो कह दें कि पिछड़ों की ओर से दिया गया दान कभी स्वीकार नहीं करेंगे। कथावाचन के लिए कानून बना दो कि यह सिर्फ वर्चस्ववादी लोग ही करेंगे। चंदा, दान, चढ़ावा स्वीकार न करें।

2- वे नहीं चाहते कि यह एकाधिकार छिने... जब सब सुन सकते हैं, तो सब बोल क्यों नहीं सकते? भागवत कथा भगवान श्रीकृष्ण से जुड़ी है। सच्चे कृष्ण भक्तों को भगवत कथा कहने से रोका जाएगा, तो कोई यह अपमान क्यों सहेगा? कुछ लोग कथावाचक में अपना एकाधिकार बनाए रखना चाहते हैं। वे नहीं चाहते कि यह एकाधिकार छिने। कथावाचन को जिन्होंने भावना की जगह व्यवसाय बना लिया है। असल समस्या वही है।

कभी घर और कभी मंदिर को धुलवाकर पीडीए का अपमान करते रहे हैं। अब तो ये वर्चस्ववादी लोग सीमाएं लांघ गए हैं। सिर तक मुड़वा दे रहे हैं। आखिर ये वर्चस्ववादी और प्रभुत्ववादी लोग ताकत कहां से पा रहे हैं? हमने सुना है कि देश की सर्वोच्च सीट पर बैठे लोगों के साथ भी अपमान हुआ। सच यह है कि पीडीए पर अत्याचार बढ़ रहा। पाल समाज की बेटी के साथ अन्याय हुआ। पिता पर मुकदमा लगाकर जेल भेज दिया, इनाम घोषित कर दिया गया।

3- PDA समाज ने अलग से कथा कहनी शुरू की तो वर्चस्व खत्म हो जाएगा हमारी पार्टी के लोग जब जा रहे थे, पुलिस लगाकर रोक दिया गया। इसका असली कारण यह है कि उन्हें लगता है कि उनके पीछे सरकार खड़ी है। लेकिन अब पीडीए समाज इसका जवाब डटकर देगा। भाजपा को लगता है कि कथावाचक पर किसी का एकाधिकार है, तो कानून बनाकर दिखा दें। जिस दिन पीडीए समाज के लोगों ने अलग से कथा कहनी शुरू कर दी, उस दिन प्रभुत्ववादी समाज का वर्चस्व खत्म हो जाएगा।

4- 2500 लोग ही पूरी सरकार चला रहे सुल्तानपुर में महेंद्र प्रताप को गोली मार दी गई। महोबा में पिछले महीने दलित नवविवाहित जोड़े को अपमानित किया गया। घर के सामने से तभी गुजर सकते हैं, जब चप्पल उतारकर जाएंगे। नहीं तो अपमानित होना पड़ेगा।

एटा में शोभा यात्रा नहीं निकालने दी गई। अम्बेडकर नगर में दलित समाज के साथ अपमान हुआ, पुलिस ने उन्हें ही पीटा। यह सब इसलिए हो रहा है कि 2500 लोग ही पूरी सरकार चला रहे हैं। सरकार में बैठे लोग कुछ भी कर सकते हैं।

5- सरकार में लोग हिस्ट्रीशीटर... अखिलेश ने बागी विधायकों को लेकर कहा- अभी आप सपा के हैं, मंत्री बनाए जाएंगे, तो आप को इस्तीफा देना पड़ेगा। मंत्री सबको बनना था। पैकेज क्या मिला था। सरकार में लोग हिस्ट्रीशीटर हैं। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री ने अपने ऊपर से केस वापस नहीं लिया क्या?

इटावा में आज क्या हुआ, पढ़िए...

अरुण दुबे बोले- कथावाचक ने अपनी जाति छिपाई ब्राह्मण महासभा के प्रदेश अध्यक्ष अरुण दुबे ने मंगलवार को इटावा के शक्ति धाम गेस्ट हाउस में बैठक की। उन्होंने जाति छुपाने के आरोपी कथावाचक और उसके साथियों के खिलाफ भी कार्रवाई की मांग की है।

इसके बाद अरुण दुबे के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बृजेश कुमार श्रीवास्तव से मुलाकात की। कथावाचक और उनके सहयोगियों के खिलाफ शिकायती पत्र सौंपा। आरोप लगाया कि

कथावाचकों ने अपनी जाति छुपाई, धार्मिक भावना भड़काई और महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया। संगठन ने चेतावनी दी कि यदि जल्द उचित कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन किया जाएगा।

महिला ने कहा- कथावाचक ने अभद्र व्यवहार किया, पूजा खंडित की पीड़ित महिला रेनु तिवारी ने भी एसएसपी से मिलकर कथावाचकों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने ने बताया, मेरे घर कथा करने आए कथावाचक ने अभद्र व्यवहार किया। उनके झोले से बरामद आधार कार्ड में उनकी जाति अग्निहोत्री लिखी मिली, इससे उनकी जाति पर संदेह हुआ। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि कथावाचक द्वारा उनकी कथा को जानबूझकर खंडित किया गया।

आरोपी युवक मनु के चाचा सोनू तिवारी ने आरोप लगाया कि कथावाचकों ने न केवल जाति छुपाई, बल्कि जानबूझकर ग्रामीणों को भ्रमित किया। उन्होंने कहा कि कथावाचकों में से एक की बहन गांव के पास ही रहती है, जिससे जानकारी मिलने के बाद ही सच्चाई सामने आई।

ब्राह्मण महासभा ने 4 सबूत दिए...

सपा जिलाध्यक्ष बोले- ब्राह्मण महासभा के आरोप निराधार समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष प्रदीप शाक्य ने ब्राह्मण महासभा के आरोपों को निराधार बताया। उन्होंने इटावा में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा, अगर कथावाचकों से कोई आपत्ति थी तो पहले शिकायत क्यों नहीं की गई। यदि कथावाचकों पर गलत तरीके से कोई कार्रवाई की गई, तो सपा भी आंदोलन के लिए बाध्य होगी।

इटावा के एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने बताया-

बकेवर प्रकरण को लेकर कुछ लोगों ने मुलाकात की है। उनकी बात सुनी गई है, लेकिन अब तक कोई लिखित शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। पुलिस निष्पक्ष जांच कर रही है और जो भी दोषी होगा, उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

अब पूरा मामला जानिए

इटावा के दादरपुर गांव में 22 जून को ब्राह्मणों ने यादव कथावाचक और उनके साथियों से मारपीट की थी, लेकिन इसका वीडियो कल सामने आया। कानपुर के कथावाचक मुकुट मणि सिंह के मुताबिक, ब्राह्मणों ने पहले उनकी जाति पूछी। जब उन्होंने बताया कि वे यादव बिरादरी से हैं, तो उन पर दलित होने का आरोप लगाते हुए धमकाया।

कहा- ब्राह्मणों के गांव में भागवत पाठ करने की हिम्मत कैसे की। इसके बाद उनकी चोटी काट दी और सिर मुंडवा दिया। एक महिला के पैर पर नाक रगड़वाई गई। उनके साथियों के साथ भी मारपीट की। उनका भी सिर मुंडवा दिया और हारमोनियम तोड़ दिया।

घटना के बाद कथावाचक सोमवार को सपा सांसद जितेन्द्र दोहरे के साथ एसएसपी से मिलने पहुंचे। SSP के आदेश पर कोतवाली में अतुल, मनीष, पप्पू बाबा और डीलर पर नामजद और 50 अज्ञात के खिलाफ मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है।

Dainik Bhaskar

अपराध: इटावा में कथावाचक के साथ बर्बरता पर राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने लिया संज्ञान, नोटिस जारी

https://www.bhaskarhindi.com/other/news-1154992

24 जून 2025

नई दिल्ली, 24 जून (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के इटावा जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक धार्मिक कथावाचक के साथ उसकी पिछड़ी जाति के कारण बर्बरता और अपमानजनक व्यवहार किए जाने की शिकायत दर्ज की गई है। इस मामले में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने कड़ा रुख अपनाते हुए उत्तर प्रदेश सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी किया है और विधिसम्मत कार्रवाई के निर्देश दिए हैं।

राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो ने मंगलवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट साझा करते हुए इस घटना की जानकारी दी। उन्होंने लिखा, "उत्तर प्रदेश के इटावा में पिछड़ी जाति से होने के कारण धार्मिक कथा वाचक को पीटने, मुंडन करने व महिला के पैरों पर नाक रगड़वाकर पेशाब छिड़कने के वीभत्स कृत्य की शिकायत प्राप्त हुई है। शिकायत के आधार पर राज्य सरकार के अधिकारियों को नोटिस जारी कर विधिसम्मत कार्यवाही करने एवं आयोग को रिपोर्ट प्रेषित करने के निर्देश दिए गए हैं।"

बता दें कि यह घटना बकेवर थाना क्षेत्र के दादरपुर गांव की है, जहां 21 जून को एक भागवत कथा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम में कथावाचक मुकुट मणि और आचार्य संत सिंह कथा वाचन कर रहे थे। आयोजन के दौरान कुछ ग्रामीणों ने कथावाचकों की जाति को लेकर आपत्ति जताई। आरोप लगाया गया कि कथावाचकों ने स्वयं को ब्राह्मण बताकर कथा का आयोजन किया, जबकि वह अन्य जाति से हैं। इसी विवाद ने तूल पकड़ा और कुछ लोगों ने कथावाचकों के साथ मारपीट शुरू कर दी। इतना ही नहीं, उनकी इच्छा के विरुद्ध उनके बाल भी काट दिए गए। इस अमानवीय कृत्य का वीडियो किसी ने बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया।

वीडियो के वायरल होने के बाद क्षेत्र में तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई। स्थानीय लोगों और धार्मिक संगठनों ने इस घटना की कड़ी निंदा की और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने मामले को गंभीरता से लेते हुए सोशल मीडिया मॉनिटरिंग सेल को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिए। सेल ने वायरल वीडियो का संज्ञान लिया और मामले की जांच शुरू की। पीड़ित कथावाचकों की तहरीर पर संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपियों आशीष (21 वर्ष), उत्तम (19 वर्ष), प्रथम उर्फ मनु (24 वर्ष) और निक्की (30 वर्ष) को गिरफ्तार कर लिया। इनमें निक्की पर कथावाचकों के बाल जबरन काटने का मुख्य आरोप है।

एसएसपी बृजेश कुमार श्रीवास्तव ने सोमवार को बताया कि यह घटना बकेवर थाना क्षेत्र के एक गांव में आयोजित भागवत कथा के दौरान हुई, जहां कथावाचक के साथ कथित तौर पर मारपीट, अपमानजनक व्यवहार और उनकी चोटी काटने की घटना हुई। सुबह से ही सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो और शिकायत के आधार पर हमने कार्रवाई शुरू कर दी है। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) के नेतृत्व में एक

जांच टीम गठित की गई है, जो इस मामले की गहन विवेचना कर रही है। पीड़ित की पहचान कर ली गई है और सभी आरोपों की निष्पक्ष जांच की जाएगी।

उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। पुलिस इस मामले में पूरी गंभीरता से काम कर रही है। ऐसी घटनाएं सामाजिक सौहार्द को नुकसान पहुंचाती हैं। दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो।

अस्वीकरण: यह न्यूज़ ऑटो फ़ीड्स द्वारा स्वतः प्रकाशित हुई खबर है। इस न्यूज़ में BhaskarHindi.com टीम के द्वारा किसी भी तरह का कोई बदलाव या परिवर्तन (एडिटिंग) नहीं किया गया है| इस न्यूज की एवं न्यूज में उपयोग में ली गई सामग्रियों की सम्पूर्ण जवाबदारी केवल और केवल न्यूज़ एजेंसी की है एवं इस न्यूज में दी गई जानकारी का उपयोग करने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञों (वकील / इंजीनियर / ज्योतिष / वास्तुशास्त्री / डॉक्टर / न्यूज़ एजेंसी / अन्य विषय एक्सपर्ट) की सलाह जरूर लें। अतः संबंधित खबर एवं उपयोग में लिए गए टेक्स्ट मैटर, फोटो, विडियो एवं ऑडिओ को लेकर BhaskarHindi.com न्यूज पोर्टल की कोई भी जिम्मेदारी नहीं है|

Janta Se Rishta

NHRC ने पेद्दा धनवाड़ा के किसानों पर झूठे मामलों को लेकर पुलिस के खिलाफ मामला दर्ज किया

https://jantaserishta.com/local/telangana/nhrc-files-case-against-police-for-filing-false-cases-against-pedda-dhanwada-farmers-4103415

Payal 24 June 2025 2:42 PM

Hyderabad.हैदराबाद: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने जोगुलम्बा गडवाल जिले के पेड्डा धनवाड़ा गांव के किसानों के खिलाफ कथित तौर पर झूठे मामले दर्ज करने वाले पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। किसानों ने पर्यावरण और आजीविका संबंधी चिंताओं का हवाला देते हुए अपने गांव के पास इथेनॉल संयंत्र की स्थापना के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया था। 5 जून को एनएचआरसी में याचिका दायर करने वाले वरिष्ठ अधिवक्ता आई. रामा राव ने सोमवार को इस घटनाक्रम की पुष्टि की। उन्होंने आरोप लगाया कि राजोली पुलिस ने प्रदर्शनकारी किसानों पर हमला किया और उन्हें झूठे मामलों में फंसाया, और पीड़ितों के लिए मुआवजे के साथ जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

रामा राव ने कहा, "एनएचआरसी ने अपने संचार में मुझे सूचित किया कि उसने पेड्डा धनवाड़ा घटना के संबंध में एक मामला (पंजीकरण संख्या 854/36/2/2025) दर्ज किया है।" विरोध प्रदर्शन के बाद, 12 किसानों को गिरफ्तार किया गया और 40 अन्य के खिलाफ मामले दर्ज किए गए। इस घटना की नागरिक समाज और अधिकार कार्यकर्ताओं ने व्यापक आलोचना की। 18 जून को लोगों में गुस्सा तब और बढ़ गया जब कुछ तस्वीरें सामने आईं जिसमें गिरफ्तार किसानों को हथकड़ी लगाकर आलमपुर कोर्ट में घुमाया गया जबकि उन्हें जमानत मिल चुकी थी। इन तस्वीरों के बाद सोशल मीडिया पर निंदा की लहर दौड़ गई और पुलिस की जवाबदेही की मांग फिर से शुरू हो गई।

Hindustan

दिल्ली से पहुंची एनएचआरसी की टीम ने मोबाइल मेडिकल यूनिट का लिया जायजा

दिल्ली से आई नेशनल हेल्थ रिसोर्स सेंटर की तीन सदस्यीय टीम ने सदर अस्पताल में मोबाइल मेडिकल यूनिट का निरीक्षण किया। टीम ने सुविधाओं की जानकारी ली और कहा कि यह मरीजों की सुविधा के लिए है। हालांकि, यूनिट...

https://www.livehindustan.com/jharkhand/sahibganj/story-nhrc-monitoring-team-reviews-mobile-medical-unit-at-sahibganj-hospital-201750787864622.amp.html

Tue, 24 Jun 2025, 11:27:PM Newswrap हिन्दुस्तान, साहिबगंज

साहिबगंज। दिल्ली से दो दिवसीय दौरे पर पहुंची तीन सदस्यीय नेशनल हेल्थ रिसोर्स सेंटर (एनएचआरसी)की मॉनिटरिंग टीम मंगलवार को सदर अस्पताल में मोबाइल मेडिकल यूनिट का जायजा लिया। टीम में डॉ. प्रियंका, डॉ. दीपाली व डॉ. कनल थे। इस दौरान टीम ने मोबाइल मेडिकल यूनिट में मौजूद सुविधाओं के बारे में जानकारी लेते हुए एलटी से कई बिंदुओं पर पूछताछ की । टीम ने कहा कि मरीजों की सुविधा के लिए मोबाइल मेडिकल यूनिट दिया गया है। इसमें ओपीडी की सारी सुविधा उपलब्ध होनी चाहिए। करीब दो सप्ताह से मोबाइल मेडिकल यूनिट खराब रहने के चलते अस्पताल परिसर में ही खड़ी है।

इसके चलते ग्रामीण क्षेत्रों के मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। मौके पर डॉ. सतीबाबू डाबड़ा, चालक विजय आदि थे।